सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा

जो सुख में साथ दे, वे रिश्ते होते हैं
जो दुख में साथ दे, वे फरिश्ते होते हैं।

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	33°	27°
शनिवार	34°	27°
रविवार	35°	30°
सोमवार	34°	29°
मंगलवार	33°	27°
बुधवार	32°	27°
वीरवार	33°	27°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 25 JULY TO 31 JULY 2025 • VOLUME 01 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

भारत और ब्रिटेन ने किए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन और कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को बनाएगा सशक्त

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुरुवार को व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर करके भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक मज़बूत आर्थिक साझेदारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और व्यापार एवं व्यापार राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के जुड़ाव में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आर्थिक एकीकरण को मज़बूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दुनिया की क्रमशः चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध वैश्विक आर्थिक महत्व रखते हैं। भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर 6 मई 2025 को घोषित वार्ता के सफल समापन के बाद हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का संयुक्त लक्ष्य है।

सीईटीए ने ब्रिटेन को भारत के 99% निर्यात के लिए अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुंच सुनिश्चित की है, जो लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र को कवर करता है। इससे कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, खिलौने और रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों के साथ-साथ इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट और जैविक रसायन जैसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था के एक मज़बूत चालक, सेवा क्षेत्र को भी व्यापक लाभ प्राप्त होंगे। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और कानूनी सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। भारतीय पेशेवर, जिनमें ब्रिटेन में सभी सेवा क्षेत्रों में काम करने के लिए कंपनियों द्वारा तैनात पेशेवर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकार जैसे अनुबंध पर तैनात पेशेवर शामिल हैं, सरल वीज़ा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभान्वित होंगे, जिससे प्रतिभाओं के लिए ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा।

भारत ने दोहरे अंशदान समझौते पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय प्रतिभाओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। यह समझौता व्यापार को और अधिक समावेशी बनाने के लिए तैयार किया गया है। महिला और युवा उद्यमी, किसान, मछुआरे, स्टार्टअप और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक नई पहुँच प्राप्त होगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने वाले प्रावधानों द्वारा समर्थित होगी।

शाह ने किया राष्ट्रीय सहकारिता नीति - 2025 का अनावरण

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीरवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति – 2025 का अनावरण किया। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल, सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अमित शाह ने कहा कि नई सहकारिता नीति का विजन है सहकारिता के माध्यम से समृद्धि लाकर 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। उन्होंने कहा कि इस नीति का मिशन है – पेशेवर, पारदर्शी, तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व सफल छोटी-छोटी सहकारी इकाइयों को बढ़ावा देना, और प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी इकाई स्थापित करना। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र के लिए तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने के छह स्तंभ निर्धारित किए गए है जिनमें – नींव का सशक्तिकरण, जीवंतता को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता को बढ़ावा और पहुँच का विस्तार, नए क्षेत्रों में विस्तार और सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना शामिल है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पर्यटन, टैक्सी, बीमा, और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए सहकारिता मंत्रालय ने विस्तृत योजना तैयार की है। विशेष रूप से टैक्सी और बीमा क्षेत्र में बहुत कम समय में शानदार शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि नए उभरते क्षेत्रों में सहकारी इकाइयों की भागीदारी का मतलब है कि सफल सहकारी इकाइयाँ एकजुट होकर नई सहकारी इकाई बनाएँगी, जो नए क्षेत्रों में काम शुरू करेगी। इसका मुनाफा इकाइयों के माध्यम से अंततः ग्रामीण स्तर की पैक्स के सदस्यों तक पहुँचेगा। इस तरह एक बड़ा और मजबूत सहकारी इकोसिस्टम तैयार करना हमारा लक्ष्य है। साथ ही, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सहकारिता को देश के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाने का दृढ़ विश्वास स्थापित करना भी हमारा उद्देश्य है।

मैडीकल व डैंटल इंटर्नों और रैजीडैंटों के मानभत्ते में वृद्धि

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को मज़बूत करने की अटूट वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुये पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के सरकारी मैडीकल और डैंटल कालेजों में इंटर्नों, जूनियर रैज़ीडैंटों और सीनियर रैज़ीडैंटों के प्रति महीना मानभत्ते (स्टाईफंड) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वर्तमान में पंजाब के सरकारी मैडीकल और डैंटल कालेजों में इंटर्नों के 907, जूनियर रैज़ीडैंटों के 1408 और सीनियर रैज़ीडैंटों के 754 मंज़ूरशुदा पद हैं। उन्होंने कहा कि इंटर्नों के लिए मानभत्ता 15,000 रुपए से बढ़ा कर 22,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। जूनियर रैज़ीडैंटों के लिए नये मानभत्ता ढांचे में मौजूदा 67,968 रुपए प्रति महीना से बढ़ कर पहले साल में 76,000 रुपए, दूसरे साल में 77,000 रुपए और तीसरे साल में 78,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह, सीनियर रैज़ीडैंटों को उनके मौजूदा 81,562 रुपए प्रति महीना से बढ़ा कर पहले साल में 92,000 रुपए, दूसरे साल में 93,000 रुपए और तीसरे साल में 94,000 रुपए मिलेंगे।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए ज़रुरी स्रोत उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दोहराया। उन्होंने कहा कि इन मानभत्तों पर सालाना व्यय, जो वर्तमान में 204.96 करोड़ रुपए है, इस बढ़ौतरी के बाद 238.18 करोड़ रुपए हो जायेगा, जोकि सालाना लगभग 33.22 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्शाता है।

कांग्रेस-भाजपा मिलकर लूट रही : केजरीवाल

नई दिल्ली/गुजरात (जालंधर ब्रीज). आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को गुजरात के डेडियापाड़ा विधानसभा में विशाल जनसभा की। 'आप' विधायक चैतर वसावा की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित जनसभा में उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भाजपा का समय चक्र पूरा हो चुका है। अब गुजरात से भाजपा की विदाई तय है। उन्होंने एलान किया कि आगामी तालुका-पंचायत चुनाव में ''आप'' आम लोगों को टिकट देगी। अब गुजरात में 'आप' एक मजबूत विपक्ष है, जो इस बार जनता के साथ मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता को कांग्रेस से सावधान करते हुए कहा कि गुजरात में अकेले भाजपा की सरकार नहीं है, बल्कि भाजपा-कांग्रेस

की गठबंधन की सरकार चल रही है। ये दोनों मिल कर लूट रहे हैं। गरीबों के मनरेगा, सड़कों का पैसा भाजपा और कांग्रेस के नेता मिलकर लूटते हैं। स्कूलों, अस्पताल, जल, जंगल, जमीन, फ्लाईओवर, नकली शराब भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का जुड़वा धंधा है। कांग्रेस भाजपा को हराना नहीं चाहती है। क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं। अभी तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी विपक्ष है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करने के फैसले पर रोक लगाई

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर वीरवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को नजीर न माना जाए। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा था 'यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।'

विशेष अदालत ने इन 12 आरोपियों में से पांच को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनायी थी। मौत की सजा पाने वाले एक दोषी की 2021 में मौत हो गयी थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में विभिन्न स्थानों पर 11 जुलाई 2006 को हुए सात विस्फोटों में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

जालंधर में कुख्यात नशा तस्कर का अवैध निर्माण ध्वस्त

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब सरकार द्वारा नशे के विरुद्ध शुरू किए गए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत, नगर निगम जालंधर ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के सहयोग से गुरुवार को न्यू हरदयाल नगर में एक कुख्यात नशा तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई अधिकारियों द्वारा 'युद्ध नशे के विरुद्ध' के तहत अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के चल रहे अभियान के तहत की गई। इस अभियान के दौरान, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा और ए.डी.सी.पी.-1 जालंधर आकर्षी जैन तथा ए.सी.पी उत्तरी आतिश भाटिया के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने नगर निगम अधिकारियों को पुलिस सहायता प्रदान की।

पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि नगर निगम को कुख्यात नशा तस्कर विजय कुमार उर्फ लड्डू द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी। नगर निगम और पुलिस की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण किए गए ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जिससे यह कड़ा संदेश गया कि जालंधर शहर में नशे से जुड़ी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम और अन्य अपराधों के तहत कुल 20 मामले दर्ज है। उन्होंने इस कार्रवाई को ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

आयकर दिवस 2025 : डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा

जालंधर ब्रीज. आयकर केवल एक राजस्व उपकरण से कहीं अधिक है – यह एक समृद्ध और स्थिर राष्ट्र की भावना और शक्ति को ऊर्जा देता है। सभी के लिए एक समाज और अवसर का निर्माण करते हुए, यह देश की सामूहिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक वित्त वर्ष में लोगों और व्यवसायों की होने वाली कमाई पर सरकार की ओर से लगाया जाने वाला कर, भारत में आयकर, आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होता है। 'आय' शब्द में विभिन्न स्रोत शामिल हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 2(24) के अंतर्गत विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। भारत के वित्तीय इतिहास में 24 जुलाई को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने के उपलक्ष्य पर आयकर दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1860 में सर जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। इसने 1922 के आयकर अधिनियम के लिए आधार तैयार किया, जिसने सही मायने में एक संरचित कर प्रणाली की स्थापना की, जिसने विभिन्न आयकर प्राधिकरणों को औपचारिक रूप दिया और एक व्यवस्थित प्रशासन ढांचे की नींव भी रखी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम (1924) ने भारतीय कराधान फ्रेमवर्क को मजबूत किया, जिसने आयकर अधिनियम के प्रशासन के लिए एक वैधानिक इकाई की स्थापना की। 1981 में कंप्यूटरीकरण की शुरुआत ने प्रमुख तकनीकी अपग्रेडेशन किया, जिसकी शुरुआत कर चालानों की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग से हुई। 2009 तक, थोक में कर रिटर्न को संभालने के लिए बेंगलुरु में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना की गई। सीपीसी एक क्षेत्राधिकार-मुक्त, तकनीक-संचालित तरीके से संचालित होता है, जो आधुनिकीकरण का एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह दिन भारत के कर प्रशासन के विकास की याद दिलाता है और एक सुव्यवस्थित एवं नागरिक-केंद्रित प्रणाली के निर्माण के लिए सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक ऐसा फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल प्रमुख तौर पर किसी व्यक्ति की आय और आयकर विभाग को लागू कर के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में आय कमाने वाले हर व्यक्ति और व्यवसाय को दाखिल किया जाना चाहिए। यह कर योग्य आय, कर देयता और कर कटौती के दावों का निर्धारण करने में मदद करती है। बीते 5 वर्षों में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या में 36% की बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9.19 करोड़ आईटीआर (अपडेट किए गए रिटर्न सहित) दाखिल किए जाएंगे, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह संख्या 6.72 करोड़ थी। यह निरंतर बढ़ोतरी बढ़ते करदाता आधार और स्वैच्छिक अनुपालन को दर्शाती है। अनुपालन में सुधार और दोहराव को खत्म करने के लिए 2017 में पैन को आधार से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, हाल के सालों में, 2009 में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) और 2012 में टीडीएस रिकॉन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम (टीआरएसीईएस) की स्थापना जैसी पहलों से क्रमशः आईटीआर की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग और रिफंड जारी करने तथा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के असंतुलन को ठीक करने करने में मदद मिली है। इसके अतिरिक्त, 2019 में शुरू की गई फेसलेस एसेसमेंट योजना का उद्देश्य ऑटोमेटेड रैंडम एलोकेशन और इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसी सुविधाओं के माध्यम से करदाता (कर निर्धारिती) और कर अधिकारी (कर निर्धारण अधिकारी) के बीच फिजिकल इंटरफेस को खत्म करके पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

नवंबर 2021 को आयकर वेबसाइट के कंप्लायंस पोर्टल पर वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) लागू किया गया, जो पूरे वित्त वर्ष में करदाताओं की वित्तीय गतिविधियों की जानकारी देता है, जिसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस), शेयर बाजार लेन-देन, म्यूचुअल फंड निवेश और अन्य प्रकार के वित्तीय डेटा से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं। आयकर विभाग ने 'पहले विश्वास करो और बाद में जांच करो' के सिद्धांत को अपनाया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत, निम्नलिखित नज सिद्धांत और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी हो जाता है। आयकर विभाग को करदाताओं की ओर से विभाग में दाखिल किए गए रिटर्न में निहित डेटा के अतिरिक्त वित्तीय डेटा भी प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी, तलाशी और जब्ती की कार्रवाइयों के निष्कर्षों और डेटा विश्लेषण की सहायता से पहचाने जाने वाले पैटर्न की मदद से कर चोरी के पैटर्न या अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। एनयूडीजीई (नज) का अर्थ है करदाताओं का मार्गदर्शन और लागू करने के लिए डेटा का गैर-हस्तक्षेपकारी इस्तेमाल, जो कि एक नज सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यवहारिक अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान पर निर्मित है, जो एक सूक्ष्म सुझाव, प्रभाव या हस्तक्षेप को संदर्भित करता है और लोगों के व्यवहार को उनकी पसंद की स्वतंत्रता को सीमित किए बिना, एक पूर्वानुमानित तरीके से बदल सकता है।

वित्त अधिनियम, 2022 के जरिए जोड़ी गई धारा 139(8ए) करदाताओं को 1 अप्रैल 2022 से संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से 24 महीनों के भीतर अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है। वित्त अधिनियम, 2025 के जरिए इस प्रावधान में संशोधन किया गया है ताकि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति से 24 महीनों से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया जा सके। यह संशोधन करदाता को मूल रूप से दाखिल किए गए रिटर्न में गलतियों को अतिरिक्त टैक्स के भुगतान के साथ, लेकिन बिना किसी दंडात्मक दायित्व के, सुधारने का मौका देता है। वित्त वर्ष 2020-21 में, कोविड महामारी से असर के बावजूद, कुल सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 12.31 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 16.34 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह रुझान 2022-23 और 2023-24 में भी जारी रही, और यह राशि क्रमशः 19.72 लाख करोड़ और 23.38 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह बढ़ोतरी आर्थिक सुधार और कर संग्रह में बेहतर दक्षता के मेल से हुई है।

वित्त वर्ष 2024-25 तक, कुल सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 27.02 लाख करोड़ रुपये (प्रोविजनल, 31 मार्च, 2025 तक) के उल्लेखनीय आंकड़े तक पहुंच गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में करदाताओं के लिए कई राहत उपाय किए गए हैं, जो सरकार के विकास-आधारित दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। नई कर व्यवस्था के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाता 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ लेने के बाद 12.75 लाख रुपये से अधिक की आय पर शून्य कर का भुगतान करेगा। कर छूट को स्लैब दर में कमी के लाभ के साथ जोड़ दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कोई कर देयता नहीं होगी। इस पहल से, मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के लिए, घरेलू खपत, खर्च और निवेश में बढ़ोतरी होगी।

भारत के इस राज्य में रहते हैं सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन

Nagaland भारत के लगभग हर हिस्से में नॉनवेज खाने के शौकीन लोग मिल जाएंगे। लेकिन दुनियाभर में इसकी गिनती वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाने वाले देशों की लिस्ट में होती है। जबकि भारत का एक स्टेट ऐसा है जहां की एक प्रतिशत से भी कम जनसंख्या वेजिटेरियन फूड...

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

भारत का हर राज्य अपने स्पेशल खानपान और डिशेज के लिए भी जाना जाता है। फिर चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान, पंजाब हो महाराष्ट्र। इन शहरों में मिलने वाले व्यंजनों का इतिहास भी कई साल पुराना होता है। इन डिशेज से उस शहर या एरिया के लोगों की खानपान की आदतों और पसंद का भी पता चलता है। दुनिया के टॉप देशों की लिस्ट में इंडिया शामिल है।

जहां ज्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। लेकिन फिर भी देश के नॉर्थ ईस्ट और साउथ के हिस्से में काफी जनसंख्या नॉन वेजिटेरियन है। वहीं एक राज्य ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और यहां पर वेजिटेरियन लोग की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम है। जानें कौन सा है वो स्टेट।

नागालैंड में 99.8 फीसदी लोग है नॉन वेजिटेरियन

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-4) ने 2015-16 में सर्वे किया था। जिसमे पता चला था कि लगभग 78 प्रतिशत महिलाएं 70 प्रतिशत पुरुष फिश, चिकन और मीट साप्ताहिक खाते हैं। वहीं एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा मीट का कंज्शन होता है। वो है नागालैंड, जहां पर रहने वाले लगभग 99.8 प्रतिशत लोग नॉनवेजिटेरियन है। वहीं इस राज्य से थोड़ा ही पीछे पश्चिम बंगाना है। जहां पर लोग 99.3 प्रतिशत ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। जबकि केरल में 99.1 प्रतिशत जनसंख्या मीट खाती है। तो इन स्टेट में अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे तो आपको वेजिटेरियन खाने के बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे। वहीं एक स्टेट ऐसा भी है जहां की ज्यादा आबादी पूरी तरह से वेजिटेरियन है।

सबसे कम मीट खाने वाला राज्य

वहीं साउथ इंडिया में कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां सबसे कम लोग यानी 81.2 प्रतिशत लोग नॉन वेजिटेरियन है।

सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं इस राज्य में

राजस्थान ऐसा राज्य हैं जहां पर कल्चरल और जैन धर्म का इफेक्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा लोग वेजिटेरियन है। यहां की लगभग 71.17 प्रतिशत जनसंख्या वेजिटेरियन है।

1% से भी कम लोग मिलेंगे वेजिटेरियन

LIFE TRUTHS

हर किसी को जानने चाहिए जीवन के 5 कड़वे सच, हमेशा खुश रहेंगे और खुलकर जीएंगे

यकीन मानिए खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो कुछ चीजों को जानने की और उन्हें एक्सेप्ट करने की। आइए जानते हैं जिंदगी के कुछ कड़वे सच, जिन्हें जितनी जल्दी जान लेंगे उतना खुश रहेंगे।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, लेकिन फिर भी कई बार दुख, परेशानी और तनाव हमें घेर ही लेते हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम जीवन के कुछ बेहद सरल लेकिन गहरे सच को नजरअंदाज कर देते हैं। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, वो छोटी-छोटी बातों में उलझता नहीं और हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। जबकि जो इंसान इन सच्चाइयों को नजरअंदाज करके बेवजह की उम्मीद लगाए बैठा रहता है, उसे दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। यकीन मानिए खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है तो कुछ चीजों को जानने की और उन्हें एक्सेप्ट करने की। आइए जानते हैं जीवन से जुड़े इसी सच को।

हर चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता

हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हर परिस्थिति वैसी बने जैसी हम चाहें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होतीं, जैसे-पूरी मेहनत के बाद भी फल ना मिलना, किसी दूसरे का आपके साथ बुरा व्यवहार करना या अचानक कोई मुश्किल खड़ी हो जाना। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना नामुमकिन है, तो मन को शांति मिलने लगती है। नियंत्रण की जरूरत कम हो जाती है और हम चीजों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। यही बात हमारी चिंता को घटाकर खुश रहने की राह खोलती है।

परिवर्तन संसार का नियम है

कहने को तो ये बात बेहद छोटी है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। लोग ये बात सुन तो लेते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं होते कि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं।

अच्छे दिन आते हैं और चले भी जाते हैं, वैसे ही बुरे वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होते। अगर हम इन बातों को समझ लें कि हर चीज बदलने वाली है, तो हम दुख के समय टूटते नहीं और सुख के समय घमंड नहीं करते। परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मानना हमें संतुलित बनाए रखता है और लाइफ के इस बैलेंस में ही सच्चा सुख छिपा हुआ है।

तुलना करना दुख की सबसे बड़ी जड़ है

इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसी और की जिंदगी को देखकर, खुद को कम आंकने लगता है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में तो ये चीजें और भी बढ़ गई हैं। अगर सुखी जीवन जीना है तो दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग-अलग होता है। जब दो लोगों के चेहरे एक से नहीं होते तो भला दो इंसानों की जिंदगी एक जैसी कैसे हो सकती है। बस ये छोटी सी बात जो समझ जाता है, उसका जीवन बहुत आसान और सुलझा हुआ हो जाता है।

सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता

जीवन में सब कुछ ठीक हो, हर काम बिना रुकावट के पूरा हो, ऐसी उम्मीद करना भी दुख का एक कारण है। असल जिंदगी में अधूरे काम, अधूरे सपने और उलझने हमेशा रहेंगी। कई बार परफेक्शन का पीछा करना ही दुख का कारण बन जाता है। जब हम लाइफ की इसी अनसर्टेनिटी को अपनाते हैं, तो हम प्रेजेंट में जीना सीखते हैं और यही प्रेजेंट हमें खुश रहने का रास्ता दिखाता है।

हर नया दिन ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है

हम अक्सर भविष्य की चिंता में या बीते कल के पछतावे में खो जाते हैं, जो हमारे दुख का एक बड़ा कारण बन जाता है। लेकिन हर किसी को समझना चाहिए कि हर नया दिन, जीवन की नई शुरुआत है।

ईश्वर हमें एक नया दिन जीने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उसे भगवान का एक खूबसूरत तोहफा समझकर नई एनर्जी के साथ जीना चाहिए। जो इंसान हर नए दिन को नई शुरुआत मानकर जीना शुरु कर देता है, उसके जीवन के दुख खुद ब खुद कम हो जाते हैं।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

लंबी या गोल, कौन सी लौकी खरीदें? जानें स्वाद और सेहत के लिए सही कैसे चुनें

आमतौर पर दो तरह की लौकी मिलती है, गोल और लंबी। ऐसे में अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी लौकी स्वाद और सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद है। चलिए जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है-

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

गर्मियों में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने वाली सब्जियों की बात हो तो लौकी का नाम सबसे पहले आता है। बेहद साधारण दिखने वाली ये सब्जी गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। मार्केट में आमतौर पर दो तरह की लौकी मिलती है, गोल और लंबी। ऐसे में अक्सर लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी लौकी स्वाद और सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके मन में भी गोल और लंबी लौकी को लेकर इस तरह की कन्फ्यूजन रहती है तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सी लौकी ज्यादा फायदेमंद है।

गोल और लंबी लौकी में अंतर

मार्केट में अक्सर गोल और लंबी दो तरह की लौकी देखने को मिल जाती हैं। जहां गोल लौकी का स्वाद हल्का मीठा और काफी स्वादिष्ट होता है, वहीं लंबी लौकी का स्वाद थोड़ा फीका हो सकता है। गोल लौकी जल्दी पक जाती है और इसकी सब्जी काफी सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाली बनती है, जिस वजह से यह दोपहर और रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके मुकाबले, लंबी लौकी का आकार बड़ा और बनावट थोड़ी सख्त होती है, जिसके कारण इसे पकाने में ज्यादा समय लग जाता है।

कई बार लंबी लौकी हाईब्रिड या इंजेक्टेड किस्म की भी हो सकती है, जिससे ना केवल इसका स्वाद प्रभावित होता है, बल्कि इसकी पौष्टिकता में भी गिरावट आ सकती है। हालांकि, लंबी लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादातर लोग जूस या सूप बनाने के लिए करते हैं। यह शरीर को ताजगी देती है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है।

गोल या लंबी, कौन सी लौकी ठीक

गोल और लंबी लौकी दोनों ही पोषण से भरपूर होती हैं। लेकिन अगर आप स्वाद, पाचन और स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो गोल लौकी बेहतर मानी जाती है। एक तो ये जल्दी पकती है, दूसरा स्वाद में हल्की मीठी होती है और पचाने में भी आसान है। वहीं लंबी लौकी को जूस या सूप के लिए उपयोग करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में अगली बार जब भी आप लौकी खरीदें, तो अपनी जरूरत के अनुसार सही लौकी का चुनाव करें।

कैसे चुनें सही लौकी

सही लौकी चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब भी आप बाजार में लौकी खरीदने जाएं, तो सबसे पहले उसके बाहरी हिस्से को देखें। लौकी की त्वचा चिकनी और ताजा दिखनी चाहिए और उसकी डंठल हरी और नर्म होनी चाहिए। अगर डंठल सूखी या टूट चुकी हो, तो यह संकेत हो सकता है कि लौकी बासी है। लौकी को हाथ में लेकर देखें कि वह सख्त और सूखी तो नहीं है क्योंकि ऐसी लौकी पकने में समय लेती है और स्वाद में भी फीकी हो जाती है।

लौकी खाने के फायदे

लौकी चाहे गोल हो या लंबी, यह पोषण से भरपूर होती है। इसमें फाइबर, पानी, कई तरह के विटामिन, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सभी तत्व शरीर को ऊर्जा देने, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करते हैं। खासकर गोल लौकी का हल्का मीठा स्वाद और जल्दी गलने वाली प्रकृति इसे पचाने में आसान बनाती है, जिससे पेट की समस्याओं से राहत मिलती है।

बच्चे की परवरिश में मददगार साबित हो रहे हैं वर्चुअल परिवार

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बच्चे की परवरिश कोई बच्चों का खेल नहीं। उसमें समय, उत्साह, ललक के साथ-साथ एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है- और वह है तजुर्बा। जो बच्चे की मां को मिलता है घर के बुजुर्गों से यानी दादा-दादी, नाना-नानी से। बच्चा रात भर रोता क्यों है? वह भर पेट दूध तो पी रहा है? वह कब चलेगा? उसके दांत कब निकलेंगे? नए अभिभावक के मन में उमड़ रहे ऐसे तमाम सवालों के जवाब दादी-नानी के पास पहले से मौजूद रहते हैं। अफसोस की बात है कि आजकल सभी बच्चों को दादी-नानी या संयुक्त परिवार का साथ नहीं मिल पाता। नतीजा, माता-पिता अकेले ही बच्चे की परवरिश करने के लिए मजबूर हैं।

आंकड़े भी इसकी तसदीक करते हैं। भारत में 2022 तक पचास फीसदी परिवार एकल हो चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में 88 फीसदी एकल परिवार हैं, जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से महरूम हैं। ऐसे में परवरिश से जुड़ी चुनौतियों, चिंताओं और सवालों के जवाब तलाशने के लिए माता-पिता ने नया तरीका खोजना शुरू कर दिया है। यह चलन है ऑनलाइन पेरेंटिंग ग्रुप्स का, जिन्हें वर्चुअल विलेज ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है।

क्या है परवरिश का वर्चुअल विलेज?

सबसे पहला सवाल यह उठता है कि भला ये कैसा गांव है? तेजी से बदलती दुनिया में जब सब कुछ ऑनलाइन है, तो बच्चे की परवरिश में हाथ बंटाने के लिए भी तकनीक सहयोगी हो रही है। ऑनलाइन मंचों पर कई ऐसे ग्रुप हैं, जहां माता-पिता, दादा-दादी, रिश्तेदार-दोस्त और एक्सपर्ट सब एक-दूसरे से ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। इन ऑनलाइन मंच पर हर उम्र के बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और परवरिश से जुड़ी समस्याओं पर खुला संवाद किया जा सकता है, सलाह ली जा सकती है। यही है परवरिश का वर्चुअल विलेज।

कुछ यूं हुई शुरुआत : जब समस्या होती है, तो उसका समाधान भी निकल आता है। नई मांओं की समस्याओं के समाधान का ही नतीजा है वर्चुअल विलेज ग्रुप्स। इनकी शुरुआत बच्चे की परवरिश से जुड़ी समस्याओं से दो-चार होती मांओं ने दूसरी मांओं की मुश्किलें आसान करने के इरादे से की। इस तरह के ग्रुप्स की शुरुआत 2010 में फेसबुक पर हुई। स्तनपान, मातृत्व, पालन-पोषण से जुड़े सवालों का जवाब देने वाला भारतीय ग्रुप 2013 में ब्रेस्टफीडिंग सपोर्ट फॉर इंडियन मदर्स नाम से शुरू हुआ।

सावन में क्यों नहीं खाते नॉनवेज, धर्म ही नहीं साइंस से भी जुड़ी है खास वजह

FOOD अकसर लोग भोजन की इन मान्यताओं को सिर्फ धार्मिक नियम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सावन में भोजन को लेकर बताए गए नियमों के पीछे साइंस के भी कई तर्क छिपे हुए हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे महीने भोलेबाबा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और उपवास करते हैं। इस दौरान खाने पीने को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं।

जिनका पालन ना करने पर सेहत और आस्था दोनों को नुकसान होता है। जी हां, सावन के महीने में कुछ लोग प्याज-लहसुन से दूरी बना लेते हैं तो कुछ नॉनवेज खाने से परहेज करते हैं। हालांकि अकसर ज्यादातर लोग भोजन की इन मान्यताओं को सिर्फ धार्मिक नियम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सावन में भोजन को लेकर बताए गए नियमों के पीछे साइंस के भी कई तर्क छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं सावन के महीने में नॉनवेज फूड खाने से परहेज क्यों करना चाहिए।

पाचन संबंधी दिक्कतें

सावन के महीने में ज्यादातर लोग धार्मिक कारणों की वजह से नॉनवेज नहीं खाते हैं लेकिन इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। दरअसल, बरसात के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने से पाचनशक्ति कमजोर हो जाती है। जबकि नॉन वेज फूड को पचाने में अधिक समय लगता है। डाइजेशन कमजोर होने की वजह से भोजन देर से या अच्छी तरह नहीं पच पाता है, जिससे नॉन-वेज फूड आंतों में सड़ने लगते हैं और व्यक्ति के लिए पेट संबंधी दिक्कतें गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और भारीपन के साथ फूड प्वाइजनिंग का खतरा भी बढ़ जाता है।

दूषित पानी

बारिश के समय में नदियों और तलाब का पानी सामान्य दनिों से ज्यादा संक्रमति और दूषित होता है। जिसका सीधा असर मछलियों पर पड़ता है। दूषित पानी में रहने वाली मछलियां हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमित हो सकती हैं, जिनका सेवन करने से सेहत खराब हो सकती है।

जानवर भी हो जाते हैं बीमार

सावन के महीने में लगातार बारिश होने से वातावरण में कीड़े, मकोड़े की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में कई जानवर घास-फूस के साथ बहुत सारे जहरीले कीड़ों का भी सेवन कर लेते हैं। जो उन्हें संक्रमित करके बीमार बना देते हैं। ऐसे जानवरों का मांस खाने से शरीर को नुकसान होता है।

हार्मोनल समस्याएं

बारिश का मौसम खासतौर पर मछलियों के लिए प्रजनन का समय होता है। ऐसे में गर्भधारण की हुई मछली का सेवन करने पर हार्मोनल समस्याएं हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ मछलियों में पारा का स्तर अधिक हो सकता है। पारा एक भारी धातु है जो तंत्रिका तंत्र के विकास को प्रभावित कर सकती है।

संक्रमण का खतरा

सावन के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने की वजह से संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बना रहता है। ये संक्रमण जानवरों को भी हो सकता है। ऐसे में जानवरों से होने वाले कसिी भी संक्रमण से बचने के लिए नॉन वेज से बचने की सलाह दी जाती है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

आम आदमी के क्षितिज को अनुप्राणित करती है भारत की अंतरिक्ष यात्रा

जालंधर ब्रीज . इसकी शुरुआत बमुश्किल दिखाई दे रही एक दरार से हुई—जो फाल्कन-9 बूस्टर की प्रेशर फीडलाइन के वेल्ड जॉइंट में छिपी हुई थी। यह अंतरिक्ष उड़ान की विशाल मशीनरी में संभवत: एक छोटी सी खामी रही होगी। लेकिन भारत के लिए, यह निर्णायक घड़ी थी। इसरो के हमारे सचेत और अटल वैज्ञानिकों ने जवाब माँगा। उन्होंने कामचलाऊ उपायों की बजाए, मरम्मत पर ज़ोर दिया और ऐसा करके, उन्होंने न सिर्फ़ एक मिशन की रक्षा की बल्कि—एक सपने की भी हिफाजत की ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह
(केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री)

उस सपने ने 25 जून, 2025 को उड़ान भरी, जब भारतीय वायु सेना के अधिकारी और इसरो-प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, एक्सिओम-4 मिशन के ज़रिए कक्षा में पहुँचे। एक दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से जुड़कर, वह —न सिर्फ़ अंतरिक्ष में, बल्कि मानव-केंद्रित विज्ञान, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के भविष्य में भी भारत की अगली बड़ी छलांग का चेहरा बन गए।

यह कोई रस्मी यात्रा नहीं थी। यह एक वैज्ञानिक धर्मयुद्ध था। शुक्ला अपने साथ सात माइक्रोग्रैविटी प्रयोग लेकर गए थे। इनमें से प्रत्येक प्रयोग को भारतीय शोधकर्ताओं ने उन सवालों के उत्तर जानने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया था, जो न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, बल्कि हमारे समूचे देश के किसानों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीजों के अंकुरित होने के बारे में विचार कीजिए। यह सुनने में सरल, लगभग काव्यात्मक प्रतीत होता है। लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं। अंतरिक्ष यान के सीमित क्षेत्र में, जहाँ पोषण का प्रत्येक ग्राम मायने रखता है, वहाँ यह समझना कि माइक्रोग्रैविटी में भारतीय फसलें कैसे व्यवहार करती हैं, लंबी अवधि के मिशनों के लिए चालक दल के आहार को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पृथ्वी पर, विशेष रूप से मृदा क्षरण और जल की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में, ऊर्ध्वाधर खेती और हाइड्रोपोनिक्स में नवाचारों को प्रेरित कर सकता है।

इसके अलावा भारतीय टार्डिग्रेड्स का अध्ययन—इन सूक्ष्म जीवों को इनकी मजबूती के लिए जाना जाता है। सुप्तावस्था से जागे इन सूक्ष्म जीवों का अंतरिक्ष में जीवित रहने, प्रजनन और जेनेटिक एक्सप्रेशन की दृष्टि से अवलोकन गया। उनका व्यवहार जैविक सहनशक्ति के रहस्यों को उजागर कर सकता है, जो टीके के विकास से लेकर जलवायु-प्रतिरोधी कृषि तक, हर चीज़ में सहायक हो सकता है।

शुक्ला ने मायोजेनेसिस प्रयोग भी किया। इस प्रयोग में इस बात की पड़ताल की गई कि मानव मांसपेशी कोशिकाएँ अंतरिक्ष की परिस्थितियों और पोषक तत्वों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देती हैं। ये निष्कर्ष मांसपेशीय क्षय के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, जिससे न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को, बल्कि वृद्ध रोगियों और आघात या ट्रामा से उबर रहे लोगों को भी लाभ होगा।

अन्य जारी प्रयोगों में सायनोबैक्टीरिया की वृद्धि—ये ऐसे जीव हैं, जो संभवत: किसी दिन अंतरिक्ष में जीवन-रक्षक प्रणालियों की सहायता कर सकते हैं—तथा चावल, लोबिया, तिल, बैंगन और टमाटर जैसे भारतीय फसलों के बीजों का माइक्रोग्रैविटी के संपर्क में आना शामिल है। इन बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया जाएगा ताकि वंशानुगत परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सके, जिससे संभावित रूप से चरम वातावरण के अनुकूल नई फसल किस्में विकसित हो सकें।

यहाँ तक कि मानव-मशीन संपर्क को भी परखा गया। शुक्ला ने यह समझने के लिए वेब-आधारित आकलन किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ बातचीत करने की हमारी क्षमता को माइक्रोग्रैविटी किस प्रकार प्रभावित करती है - जो भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और अंतरिक्ष यान के लिए सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस डिजाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है।

ये कोई अमूर्त प्रयास नहीं हैं। ये समाज के लिए विज्ञान के भारतीय लोकाचार में गहराई से निहित हैं। एक्सिओम-4 का हर प्रयोग पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है—चाहे वह ओडिशा का कोई जनजातीय किसान हो, शिलांग का कोई स्कूली बच्चा हो, या लद्दाख का कोई फ्रंटलाइन डॉक्टर हो।

इस मिशन ने वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत के बढ़ते कद को भी दर्शाया। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हमारे द्वारा ज़ोर दिए जाने ने स्पेसएक्स को एक संभावित विनाशकारी खामी की पहचान करने और उसे ठीक करने में मदद की। नासा, ईएसए और एक्सिओम स्पेस के साथ हमारा सहयोग समान साझेदारी के एक नए युग को दर्शाता है, जहाँ भारत केवल भाग ही नहीं ले रहा है, बल्कि नेतृत्व भी कर रहा है।

पूरे मिशन के दौरान, इसरो के फ़्लाइट सर्जनों ने शुक्ला के स्वास्थ्य पर नज़र रखते हुए उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखा। वे पूरे जोश में रहे और लखनऊ से लेकर त्रिवेंद्रम, बैंगलोर से लेकर शिलांग तक, पूरे भारत के छात्रों से बातचीत करते रहे और युवा मन में विज्ञान और अंतरिक्ष की संभावनाओं के प्रति उत्साह जगाते रहे।

शुक्ला अब लौट आए हैं, और वह अपने साथ प्रचुर मात्रा में डेटा, नमूने लाए हैं और उनके द्वारा लाई गई अंतर्दृष्टि भारत के आगामी गगनयान मिशन और भारत अंतरिक्ष स्टेशन को शक्ति प्रदान करेगी।

यह सिर्फ़ एक अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं है। यह एक राष्ट्र के उत्थान की बात है। यह अंतरिक्ष विज्ञान को जनसेवा में बदलने की बात है। यह माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान के लाभ भारत के कोने- कोने तक —दूरदराज के गाँवों में सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर शहरी अस्पतालों में पुनर्योजी चिकित्सा तक पहुँचाना सुनिश्चित करने की बात है ।

हमारे प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी के शब्दों में, गगनयान का आशय है किसी भारतीय को भारतीय साधनों के द्वारा अंतरिक्ष में पहुँचाना। एक्सिओम-4 एक पूर्वाभ्यास है, अवधारणा का प्रमाण है, आकांक्षा और उपलब्धि के बीच का सेतु है।

और जब हम तारों को देखते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ़ अचरज भरी निगाहों से ही नहीं निहारते, बल्कि इरादे से देखते हैं। क्योंकि भारत के लिए आकाश कोई सीमा नहीं, बल्कि प्रयोगशाला है।

नशा मुक्त युवा, विकसित भारत का सारथी

जालंधर ब्रीज . कहा जाता है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो उसका युवा सशक्त और समर्थ होना चाहिए। विश्व में भारत ऐसा देश है, जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी युवा शक्ति ही निभाएगी। देश के विकास की रफ्तार युवाओं की ऊर्जा, विचार और संकल्प से ही तय होती है।

लेकिन आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, अपने युवाओं को नशे की लत से दूर रखना। वर्तमान में युवा वर्ग नशे के घेरे में आता जा रहा है। यह नशा न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि करियर, सपनों और देश की ताकत को भी प्रभावित कर रहा है। एक स्टडी के मुताबिक, भारत में 10 से 24 वर्ष की उम्र के हर 5 में से 1 युवा ने कभी न कभी ड्रग्स का सेवन किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की रिपोर्ट के अनुसार, 8.5 लाख से अधिक बच्चे ड्रग्स की लत का शिकार हैं। ये आंकड़े बेहद डरावने और चिंतन योग्य हैं।

ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के खात्मे के लिए भारत सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। 2020 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत की। नशे की लत को रोकने और पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने राष्ट्रीय नशा मुक्ति केंद्र (IRCAs) और आउटरीच-कम-ड्रॉप-इन सेंटर (ODICs) की स्थापना की। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग माफिया के विरुद्ध सशक्त ऑपरेशन्स किए। साथ ही, देशभर में युवाओं की काउंसलिंग हेतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में भी स्थानीय प्रशासन, गैर-सरकारी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से नशे के विरुद्ध कई बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं।

भारत इस लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में MY Bharat ने एक बड़ी पहल की है। बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से 19 से 20 जुलाई तक 'युवा आध्यात्मिक समिट' का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम होगा 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत'। वाराणसी के पावन घाटों पर आयोजित होने वाले इस समिट का उद्देश्य, एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाना है, जो युवाओं के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान को सशक्त बनाए।

डॉ. मनसुख मांडविया
(केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार)

इस समिट में देशभर की 100 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के युवा प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं भी इसमें सहभागिता करेंगी। इसके माध्यम से युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा, जहां वो अपनी आवाज़ को सरकार और नीति निर्माताओं तक पहुँचा सकेंगे।

इस समिट में देश की नशे के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत करने के लिए विभिन्न सेशन्स आयोजित किए जाएंगे। इसमें नशे की प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति, प्रकार, पीड़ितों की जनसांख्यिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और सरकार तथा MY Bharat के युवा स्वयंसेवकों की भूमिका जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श और चर्चा होगी। साथ ही नशे की लत से उबरने वाले युवाओं की प्रेरक कहानियां और उनके अनुभव भी साझा किए जाएंगे, ताकि अन्य युवा उनसे प्रेरणा ले सकें।

अंत में एक 'काशी डिक्लेरेशन' जारी किया जाएगा, जो अगले पांच वर्षों के लिए नशा मुक्ति अभियान का रोडमैप होगा। इसमें यह तय किया जाएगा कि युवाओं को किस प्रकार नशे से दूर रखा जाए, नशे की गिरफ्त में आए लोगों की कैसे सहायता की जाए और पूरे देश में जागरूकता अभियान को किस तरह तेज किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश की अमृत पीढ़ी के सपनों का भारत बनाने की बात करते हैं। उनके विजन के अनुरूप, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा उठाया गया यह कदम, एक समग्र और प्रभावशाली पहल का उदाहरण बनेगा। यह पहल न केवल युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में भी सशक्त भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगी।

देश को विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी युवा शक्ति की है। काशी में आयोजित होने वाला 'युवा आध्यात्मिक समिट' इस लक्ष्य की दिशा में केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभ स्थल बनेगा। यह नशे के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान को नई दिशा और ऊर्जा देगा। साथ ही, युवाओं में नैतिक मूल्यों, सामाजिक ज़िम्मेदारी और आत्म-संयम का ऐसा भाव जागृत करेगा, जो न केवल उन्हें अपने जीवन में सार्थकता देगा, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का माध्यम बनेगा। काशी की पवित्र धरती से उठने वाली यह पुकार, हर युवा के मन में जागृति और देशभक्ति का नया प्रकाश भर देगी और यही संकल्प 2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव बनेगा।

EPFO आंचलिक कार्यालय ने 110वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक आयोजित की और ELI योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला

जालंधर ब्रीज . EPFO पंजाब की 110वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक 22 जुलाई 2025 को श्रम भवन, फेज 10, मोहाली में मनवेश सिंह सिद्धू, आईएएस, श्रम आयुक्त, पंजाब सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में राजीव बिष्ट, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (PB & HP), राजीव कुमार गुप्ता, आईएएस, श्रम आयुक्त, पंजाब सरकार सहित EPFO के आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा पंजाब एवं चंडीगढ़ के पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रभारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, समिति ने पंजाब राज्य में EPFO, पंजाब के प्रदर्शन का आकलन किया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें न्यायालय के मामलों की स्थिति, मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उठाए गए कदम, संस्थानों की कवरेज पर प्रगति, राज्य सरकार विभागों के साथ डेटा साझा करना और राज्य विभाग संगठनों का प्रधान नियोक्ता पोर्टल पर पंजीकरण शामिल थे। राजीव बिष्ट, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (PB & HP) ने सूचित किया कि ELI योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका कुल बजट ₹99,446 करोड़ है। योजना दो हिस्सों में विभाजित है: भाग A में अगस्त 2025 से जुलाई 2027 के बीच पहली बार नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को ₹1 लाख तक की तनख्वाह वाले कर्मचारियों को ₹15,000 तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह भुगतान 6 और 12 महीने की सेवा के बाद दो किस्तों में किया जाएगा, और एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को पूरा करना एक प्रमुख शर्त होगी। लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा । भाग B के तहत नियोक्ताओं को अतिरिक्त नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में। नियोक्ता को हर नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह तक की राशि मिलेगी, जो कम से कम छह महीने तक कार्य करेगा। प्रोत्साहन को विनिर्माण नियोक्ताओं के लिए तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। भुगतान कर्मचारियों के लिए DBT के माध्यम से और नियोक्ताओं के PAN-लिंक्ड खातों में सीधे किया जाएगा। यह योजना सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें देश की श्रमशक्ति को औपचारिक बनाने का उद्देश्य है, ताकि भारत के करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जा सके।

वृद्धजनों को लक्ष्य बनाकर साइबर अपराध की घटनाएँ

जालंधर ब्रीज . राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों से जुड़े) के अंतर्गत दर्ज मामलों का विवरण इस प्रकार है :

देश में वृद्धजनों द्वारा दर्ज कराई गई साइबर अपराध की शिकायतों के संबंध में विशिष्ट आंकड़े एनसीआरबी द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध और वृद्धजनों के विरुद्ध साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जाँच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, इन पहलों को पूरक बनाती है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्श और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

साइबर अपराध

वर्ष	दर्ज मामले
2018	27,248
2019	44,735
2020	50,035
2021	52,974
2022	65,893

केंद्र सरकार ने वृद्धजनों के विरुद्ध साइबर अपराध सहित साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) की स्थापना की है।

आई4सी के एक भाग के रूप में, 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है, जिससे आम जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके। इस पोर्टल पर दर्ज साइबर अपराध की घटनाओं, उनकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में रूपांतरण और उसके बाद की कार्रवाई, कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है।

भारत में उपभोग मामले में घटती असमानता को आखिर क्यों सराहना मिलनी चाहिए!

सौम्य कांति घोष

जालंधर ब्रीज . हाल ही में भारत के उपभोग-आधारित गिनी गुणांक में आई गिरावट ने एक जबरदस्त चर्चा को जन्म दिया है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत का गिनी गुणांक 2011-12 में 28.8 से घटकर 2022-23 में 25.5 हो गया है। गिनी गुणांक में यह गिरावट तब और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब इसकी तुलना विशेष रूप से विश्व असमानता डेटाबेस (डब्ल्यूआईडी) के आय-आधारित अनुमानों के साथ की जाती है। असमानता संबंधी इस डेटाबेस ने 2023 में भारत के गिनी को स्पष्ट रूप से 62 के चिंताजनक स्तर पर रखा था। इस स्पष्ट असंगति को समझने के लिए अंतर्निहित आयामों, डेटा स्रोतों और वैचारिक ढांचे का गहन विश्लेषण जरूरी है। इसके बाद बात एक ऐसे तार्किक आलोचनात्मक विमर्श की आती है - जो पद्धतिगत असंगतियों को ठोस आर्थिक हकीकतों से अलग करके देखता है तथा असमानता को दूर करने के मौलिक रूप से भिन्न उपायों को एक साथ मिलाने के खतरों पर प्रकाश डालता है।

इस भिन्नता के मूल में एक महत्वपूर्ण वैचारिक अंतर है: उपभोग संबंधी असमानता और आय संबंधी असमानता के बीच का अंतर। विशाल अनौपचारिक श्रमशक्ति, व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का लेनदेन करने और तेजी से विस्तारित होती कल्याणकारी संरचना वाले भारत जैसे देश में आय अक्सर अस्थिर होती है और उसके बारे में कम रिपोर्ट की जाती है या उसे व्यापक रूप से दर्ज पाना कठिन होता है। इसके उलट, उपभोग समय के साथ अधिक सुचारू होता जाता है और यह वास्तविक जीवन स्तर को ज्यादा सही तरीके से प्रतिबिंबित करता है। विश्व बैंक का गरीबी एवं असमानता मंच (पीआईपी) राष्ट्रीय संदर्भ के आधार पर प्रयोज्य आय या उपभोग संबंधी व्यय का उपयोग करते हुए इस तर्क को अपनाता है।

सबसे पहले, यह बताना उचित होगा कि विश्व बैंक ने अपने "विश्व बैंक का असमानता संबंधी नया सूचक" शीर्षक वाले शोध-पत्र में उपभोग आधारित गिनी को आय आधारित गिनी और आय आधारित गिनी को उपभोग आधारित गिनी में बदलने का तरीका सुझाया है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 84 देश-वर्षों में, जहां उपभोग आधारित तथा आय आधारित दोनों गुणांकों के आंकड़े उपलब्ध थे, आय व उपभोग आधारित गिनी गुणांकों का औसत अनुपात 1.13 है। इस औसत अनुपात को भारत के 25.5 के उपभोग-आधारित गिनी गुणांक पर सीधे लागू करने पर लगभग 28.8 की आय आधारित गिनी हासिल होती है। परिणामस्वरुप, आय-समतुल्य मान्यताओं के तहत भारत अभी भी 12वें स्थान पर है। यह सरल अनुमान पीआईपी डाटाबेस के भीतर कल्याण के विभिन्न प्रकारों की तुलना करने का एक तरीका सुझाता है। इससे एक प्रासंगिक सवाल उठता है: इस तरीके को व्यापक रूप से स्वीकार क्यों नहीं किया गया है? इसका जवाब शायद चुनिंदा रूप से बाहरी अनुमानों पर जोर देने की प्रवृत्ति में निहित है। जब विभिन्न देशों के बीच तुलना के लिए दिए गए सरल अनुमान का उपयोग किया जाता है, तो आय के संदर्भ में मापे जाने पर भी भारत की असमानता संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में काफी कम दिखाई देती है। उपभोग आधारित कल्याण का दृष्टिकोण अपनाने वाले 48 देशों की सूची में, भारत तीसरे स्थान पर है। पीआईपी डाटाबेस में भारत का 25.5 का उपभोग आधारित गिनी गुणांक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए, चीन का उपभोग आधारित गिनी उसी डेटाबेस के अनुसार और कल्याण की उसी अवधारणा का उपयोग करते हुए 35.7 है। लगभग 10 अंकों का यह अंतर बेहद उल्लेखनीय है।

दूसरा, बड़े पैमाने वाली समाज कल्याण योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से आलोचना से दायरे से गायब क्यों है? भारत जैसे देश में सब्सिडीयुक्त भोजन, एलपीजी, आवास, ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य बीमा और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसे बड़े पैमाने वाले समाज कल्याण कार्यक्रमों ने गरीबों के जीवन स्तर को काफी हद तक बेहतर बनाया है। परिणामस्वरूप, वहां उपभोग निश्चित रूप से आय की तुलना में अधिक होगा और अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित होगा। सार्वजनिक प्रावधान के ये रूप खासतौर पर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ाते हैं। वर्ष 2025 के बजटीय अनुमान के अनुसार, विभिन्न लाभार्थी योजनाओं पर केन्द्र सरकार का व्यय 7.1 लाख करोड़ रुपये होगा तथा विभिन्न राज्य मिलकर इसमें 7.4 लाख करोड़ रुपये और जोड़ेंगे। इसका कुल योग लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपये होगा। पीएलएफएस डेटा के अनुसार, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी की औसत मासिक कमाई लगभग 21000 रुपये और स्व-नियोजित व्यक्ति की औसत मासिक कमाई लगभग 14000 रुपये है। अनियमित मजदूर की प्रतिदिन की औसत कमाई 433 रुपये है। इन अनुमानों का उपयोग करने और चार लोगों के परिवार की निर्भरता को ध्यान में रखने पर, यह प्रति व्यक्ति आय 65000 रुपये की बन जाती है। यह मानते हुए कि कुल लाभार्थी योजनाओं का 80 प्रतिशत हिस्सा नीचे के 50 प्रतिशत लोगों तक पहुंचता है, यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ तमाम गड़बड़ियों और अतिव्यापन (ओवरलैप) के बावजूद प्रति व्यक्ति 15000 रुपये प्रति वर्ष का बनता है। प्रभावी संसाधनों में लगभग 20 प्रतिशत का यह उत्थान उपभोग में बदल जाता है। इस प्रकार, इन रूढ़िवादी मान्यताओं के तहत भी, यह प्रभावी असमानता को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है। इन उपायों से गरीबी में भी नाटकीय गिरावट आई है तथा चरम गरीबी की दर 2011-12 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 2.3 प्रतिशत रह गई है। कुल 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की निम्न-मध्यम-आय रेखा पर, गरीबी 61.8 प्रतिशत से घटकर 28.1 प्रतिशत हो गई है।

डब्ल्यूआईडी के अनुमानों को बिना सोचे-समझे स्वीकार करने से पहले, क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि ये अनुमान आखिर क्या माप रहे हैं? डब्ल्यूआईडी डेटाबेस की बात करें तो, उनकी आय संबंधी मानक अवधारणा है: "कर-पूर्व, प्रतिस्थापन-पश्चात राष्ट्रीय आय" — यानी करों और हस्तांतरणों से पहले, पेंशन और बेरोजगारी लाभ जैसे सामाजिक बीमा घटकों को छोड़कर। इसका मतलब है कि वे अधिकांश गैर-अंशदायी कल्याणकारी हस्तांतरणों—जैसे कि भारत का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), खाद्य सब्सिडी, एलपीजी से जुड़ी योजनाएं, आयुष्मान भारत, ग्रामीण आवास आदि - को छोड़ देते हैं।

भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अंशदायी बीमा की तुलना में गैर-अंशदायी हस्तांतरणों पर कहीं अधिक निर्भर करती है। इन्हें डब्ल्यूआईडी की आय संबंधी अवधारणा में शामिल नहीं किया जाता, भले ही ये वास्तविक आय और क्रय शक्ति को भौतिक रूप से क्यों न बढ़ाते हों।

जब डब्ल्यूआईडी इन लक्षित योजनाओं के पुनर्वितरणात्मक प्रभाव को अनदेखा करके और राष्ट्रीय आय के शीर्ष पर स्पष्ट संकेंद्रण को बढ़ाकर भारत में असमानता को मापता है, तो इससे एक व्यवस्थित एवं नीचे की ओर जाने वाला पूर्वाग्रह पैदा होता है। इसलिए, डब्ल्यूआईडी के आय की असमानता से जुड़े ढांचे के तहत, हम अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि भारत में उत्थान की प्रमुख योजनाओं का मापी गई असमानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

दूसरे, डब्ल्यूआईडी अपने डेटाबेस को संकलित करने के लिए कर संबंधी रिकॉर्ड पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। अब यदि हम कर संबंधी रिकॉर्ड को देखें, तो लोगों की कर योग्य आय के आयकर रिटर्न (आईटीआर) संबंधी आंकड़ों का उपयोग करके अनुमान लगाया गया गिनी गुणांक यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत आय में असमानता आकलन वर्ष 2015 (वित्तीय वर्ष 2014) से लेकर आकलन वर्ष 2023 (वित्तीय वर्ष 2022) के दौरान 0.472 से घटकर 0.402 हो गई है। आकलन वर्ष 2015 (वित्तीय वर्ष 2014) में 4 लाख रुपये से कम आय वर्ग से संबंधित 43.6 प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोग निम्नतम आय वर्ग को छोड़कर ऊपर वाले वर्ग में पहुंच गए। वित्तीय वर्ष 2014 और वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान आय में हुई असमानता की तुलना से यह पता चलता है कि आय वितरण के वक्र में स्पष्ट रूप से दाईं ओर बदलाव हुआ है, जिसका अर्थ है कि निम्न आय वर्ग के लोग आबादी में अपने हिस्से के अनुरूप अपनी आय बढ़ा रहे हैं। आकलन वर्ष 2024 का घंटी के आकार का वक्र और भी कुछ कहता है!! वित्तीय वर्ष 2014 में, कुल आय में शीर्ष एक प्रतिशत का हिस्सा 1.64 प्रतिशत था। यह हिस्सा वित्तीय वर्ष 2021 में घटकर 0.77 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 1.1 की कर उछाल और कर संग्रह की घटती लागत वास्तव में बेहतर अनुपालन को दर्शाते है। इसलिए, इसे बढ़ती असमानता के रूप में समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यदि भारत के कर संबंधी आधिकारिक आंकड़े बेहतर प्रगति को दर्शाते हैं तथा बड़े पैमाने वाले उपभोग संबंधी सर्वेक्षण असमानता में निरंतर कमी का संकेत देते हैं, तो यह पूछना उचित होगा कि डब्ल्यूआईडी के अनुमान आखिर इतनी अलग कहानी क्यों बताते हैं।

यह तर्क देना कि केवल चुनिंदा रूप से बढ़ाए गए आय संबंधी अनुमानों के आधार पर भारत में असमानता गहराई से पैठी हुई है, बिल्कुल वैसा ही दावा करने जैसा है कि चूंकि राजस्थान में पानी का अभाव है, इसलिए समूचे देश में पानी का संकट है। अभाव की तरह, असमानता में एकरूपता नहीं होती है—यह आयामों, क्षेत्रों और मापन उपकरणों के आधार पर अलग-अलग होती है। लेकिन ऐसी असमानता से व्यापक प्रगति अमान्य नहीं हो जाती। संकीर्ण एवं आंशिक दृष्टिकोण के पक्ष में इन पहलुओ की उपेक्षा करने वाला कोई भी मूल्यांकन उसी प्रगति को खारिज करने का जोखिम मोल लेता है, जिसकी वह आलोचना करना चाहता है।

अब जबकि हम आगे की ओर अग्रसर हैं, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, बेहतर रिपोर्टिंग का मतलब बढ़ती असमानता नहीं है—और हमें बेहतर आंकड़ों के प्रभावों पर प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र को हमेशा अपने इस मूल प्रश्न पर लौटना चाहिए कि: कौन सी चीज निचले आधे हिस्से के जीवन से जुड़े अनुभवों को बेहतर बनाती है? इस संदर्भ में, पिछले एक दशक की भारत की कहानी शीर्ष पर होने वाले विचलन से कम बल्कि निचले स्तर पर होने वाले अभिसरण — यानी लोगों द्वारा वास्तव में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के मामले में शांत, व्यापक और मापनीय बदलाव से कहीं अधिक जुड़ी है।

(लेखक 16वें वित्त आयोग के सदस्य और भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार व भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

लैंड पूलिंग पॉलिसी का गुणगान करने वाला पुड्डा विभाग रेगुलराइजेशन पॉलिसी के डकारे हुए पैसे का हिसाब दे

• **जालंधर ब्रीज .** विशेष रिपोर्टर

पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको सत्ता में काबिज हुए तीन वर्ष से भी ज्यादा का समय हो चुका है। सरकार फ्रीबीज़ बांटने का वादा तो कर बैठी लेकिन पंजाब के विक्राल हालात देखकर सरकार इसे पूरा करने में विफल साबित हो रही है। वहीं, 1000 रुपये वाले मुद्दे पर विपक्षीय पार्टियों को हर बाय-इलेक्शन में सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है।

मौजूदा सरकार ने हताश विपक्ष के हाथ ऐसा मुद्दा दे दिया जो सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है जो विपक्षी पार्टियों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। जिस अकाली दल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान अक्सर कटाक्ष करते हुए देखे जाते हैं कि अकाली दल का नाम अब खाली दल रख देना चाहिए। इस कटाक्ष ने पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी की जारी हुई नोटिफिकेशन ने सुखबीर बादल को ऐसा मौका दे दिया जिससे जमीनी स्तर पर उन्हें गांवों में भारी समर्थन हासिल हो रहा है। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून के पहले हक में बोलना फिर उसके खिलाफ बोलने से दोगलेपन के किरदार ने गांवों में काफी नुकसान किया। जिस कारण अकाली दल को सरकार से बाहर आना पड़ा और हरसिमरत कौर बादल को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।

अब यही स्थिति भगवंत मान सरकार की बनती जा रही जो किसी समय केंद्र में शासित मोदी सरकार की बनी थी और उन्हें पंजाब के जमींदारों से माफी मांग कर तीनों कानून वापिस लेने पड़ गए थे।

यहां देखा जा रहा है जिस प्रकार जमींदारों में गुस्सा बढ़ रहा है उससे लग रहा है यह पॉलिसी भी तीनों कानून की तरह हाशिए पर जा सकती है। क्योंकि भगवंत मान पंजाब के जमींदारों को भली-भांति जानते हैं और कई बार गांवों में पड़ने वाले डल्ले का अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते रहते हैं और किसान यूनियन के भारी समर्थन और पॉलिसी के विरोध में उठ रही आवाज ने इस बात को भी हवा दे दी है कि जो पुडा विभाग लैंड पुलिंग पॉलिसी लेकर आई है वो अक्सर अवैध कालोनियों जिसकी संख्या लगभग 13000 के करीब उपभोक्ताओं को मूलभूत सुविधा दिलवाने के लिए कई बार रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेकर आई है जिसको 2013 से लेकर 2025 तक तीनों सरकारों चाहे अकाली भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार या फिर मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार हो लागू करने में पूरी तरह फेल हुई। पॉलिसी के नाम पर एकत्रित किए गए पैसे को डायवर्ट कर दुरुपयोग किया जा चुका है जोकि एक अलग जांच का विषय है। इसने पुड्डा विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकार का पुडा विभाग लोगों को सुविधा मुहैया करने के लिए बनाया गया है न कि पॉपर्टी डीलर का काम करने के लिए। जिस प्रकार से पुड्डा की नाकामियों से पहले ही लोग पीड़ित हैं सरकार की नियत चाहे अच्छी हो परंतु पुड्डा विभाग के पूर्व किरदार के कारण यह पॉलिसी अब तक फ्लॉप साबित हो रही है।

जालंधर-कपूरथला रोड पर पूडा के अंतर्गत पड़ती अवैध कॉलोनी ग्रीन फील्ड एक्सटेंशन की टूटी हुई सड़कें।

फगवाड़ा के चहेड़ू स्थित पुड्डा के अंतर्गत आती अवैध कॉलोनी हाईवे प्लाजा की दयनीय हालत।

हाईवे और सड़कों पर अनाधिकृत कट तुरंत बंद करने के निर्देश

डिप्टी कमिश्नर ने कहा- सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, डिप्टी कमिश्नर डा.हिमांशु अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राजमार्गों सहित सड़कों पर अनाधिकृत कट तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। यहाँ जिला प्रशासकीय परिसर में, डिप्टी कमिश्नर ने सचिव आर.टी.ए. बलबीर राज सिंह के साथ सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को राजमार्गों और सड़कों पर अनाधिकृत कटों की पहचान कर उन्हें तुरंत बंद करवाने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने सड़क हादसों वाली सड़कों सहित सहित उच्च जोखिम वाली चौराहों और मोड़ों की पहचान करके सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के तुरंत उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें ऐसे प्वाइंट्स पर उचित संकेत,

स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक लाइटें लगाना शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़कों में कुछ आवश्यक बदलाव करके, उनकी मुरम्मत करके तथा सड़क नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

डिप्टी कमिश्नर ने 'पंजाब सड़क सफ़ाई मिशन' के तहत जिले के विभिन्न सीनियर अधिकारियों द्वारा गोद ली गई सड़कों का निरीक्षण करने के बाद उनके ध्यान में लाए गए मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा। बैठक में आर.टी.ओ. अमनपाल सिंह के अलावा पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, नैशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रतिनिधि और सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य भी मौजूद थे।

नेशनल सैंपल सर्वे की 75वीं वर्षगांठ मनाई

जालंधर (जालंधर ब्रीज). भारत के साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नेशनल सैंपल सर्वे की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर ने वीरवार को रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में एनएसएस बूथ लगाया। इस एनएसएस बूथ में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के अधिकारियों ने एनएसएस द्वारा किए जा रहे कार्यों और सर्वेक्षणों को दर्शाने वाले पैम्फलेट, जो कि "एनएसएस - एक गौरवशाली अतीत से विकसित भारत के लिए एक आशाजनक भविष्य" थीम पर आधारित थे, को वितरित किया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों

में अरुण कुमार, सहायक निदेशक, उमेश कुमार लिम्बू, बलराम सिंह एवं श्रीमति मनीषा, राहुल शर्मा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी तथा बलविंदर कौर, सोनिका अत्री, रविंदर, चेतन कुमार और सतनाम सिंह, सर्वेक्षण प्रगणक आदि शामिल थे।

लंगर कमेटियां व सामाजिक संगठन जिला प्रशासन को करें सहयोग: ब्रम शंकर जिंपा

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

25 जुलाई से शुरु होने वाले माता चिंतपूर्णी के मेले की व्यवस्था को लेकर विधायक ब्रम शंकर जिंपा ने आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में प्रशासनिक अधिकारियों, लंगर कमेटियों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, एस.एस.पी संदीप कुमार मलिक व मेयर सुरिंदर कुमार भी मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक ब्रम शंकर जिंपा ने सभी विभागों को मेले की व्यवस्था सुचारु बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से मेले की तैयारियों को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना लंगर कमेटियों व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के बिना माता चिंतपूर्णी के मेले की व्यवस्था का सुचारु रुप से नहीं चलाया जा सकता। इस लिए लंगर कमेटियों व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की विशेष जरुरत है।

ब्रम शंकर जिंपा ने जिला प्रशासन की ओर से मेले के दौरान लंगरों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करवाने के लिए बहुत प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले में जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से 5 लाख रुपए के करीब पर्यावरण अनुकूलित प्लेट, ग्लास व चम्मच मुहैया उन लंगर सोसायटियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे जो अंजाने में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने सभी लंगर सोसायटियों से अपील करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें।

समय पर इलाज और जागरूकता से ही सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव : सिविल सर्जन

जालंधर (जालंधर ब्रीज). स्वास्थ्य विभाग जालंधर और "फुलकारी ऑल वूमेन ऑर्गनाइजेशन" के संयुक्त प्रयासों से वीरवार को सिविल अस्पताल जालंधर के 'जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केंद्र' में सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) की स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉ. गुरमीत लाल ने कैंप का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा रोग है जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और समय पर जांच से पूरी तरह रोका जा सकता है। इस मौके पर डॉ. रमन गुप्ता (जिला परिवार कल्याण अधिकारी), डॉ. वरिंदर कौर थिंद (एसएमओ- गायनी), डॉ. सतिंदर बजाज (एसएमओ), डॉ. प्रियंका, डॉ. स्वाति, डॉ. प्रभशरण कौर और डिप्टी एमईआईओ असीम शर्मा भी मौजूद रहे। सिविल सर्जन डॉ. गुरमीत लाल ने 'फुलकारी' संस्था द्वारा स्क्रीनिंग कैंप के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को

इस इलाज योग्य कैंसर से बचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर 100% इलाज योग्य है और समय पर जांच और एचपीवी टीकाकरण से इससे बचाव संभव है। सिविल सर्जन ने 'फुलकारी' संगठन के सदस्यों से अपील की कि वे गांवों में 'विलेज हेल्थ, सेनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी' (वीएचएसएनसी) के साथ तालमेल बनाकर जिले के दूर-दराज के गांवों तक भी यह जागरूकता फैलाएं और ऐसे कैंप लगाएं ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। सिविल सर्जन ने बताया कि जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित इस स्क्रीनिंग कैंप में कुल 21 महिलाओं की जांच की गई। केंद्र की एसएमओ डॉ. वरिंदर कौर थिंद ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में होने वाला एक गंभीर रोग है, जो मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) के कारण होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में असामान्य रक्तस्राव, पेट के निचले हिस्से में दर्द और संभोग के दौरान दर्द शामिल हैं। समय रहते पैप टेस्ट या एचपीवी टेस्ट करवाकर इसकी पहचान और इलाज संभव है।

'फुलकारी ऑल वूमेन ऑर्गनाइजेशन' की प्रधान अद्वैता तिवारी, हरसीरत हैनरी, अंजली दादा (मुखी कौंकर कैंसर विंग) और मैडम मनिंदर ने भी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जानकारी दी और स्क्रीनिंग के लिए प्रोत्साहित किया।

नकदी रहित प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सुविधा शुरू

फगवाड़ा (जालंधर ब्रीज). नगर निगम फगवाड़ा ने नकदी रहित प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन सिस्टम शुरू किया है। इसका उद्घाटन नगर निगम फगवाड़ा के मेयर राम पाल उप्पल और निगम कमिश्नर डॉ. अक्षिता गुप्ता आईएएस ने फेडरल बैंक के सहयोग से संयुक्त रूप से किया।

नई तैनात की गई पीओएस मशीनें टैक्स भुगतान को सुचारू बनाने, मानवीय निर्भरता को कम करने, तेज और सुरक्षित लेनदेन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो नगर निगम फगवाड़ा की स्मार्ट, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को

मजबूत करती हैं। मेयर राम पाल उप्पल ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल फगवाड़ा वासियों के लिए सुविधा बढ़ाएगी और टैक्स कलेक्शन सरल बनाने में महत्वपूर्ण सुधार करेगी।

वकील पर गोली चलाने वाला पिस्तौल सहित काबू

जालंधर (जालंधर ब्रीज). सीआईए स्टाफ कमिश्नरेट जालंधर की टीम ने एडवोकेट सिमरनजीत सिंह पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने वाले व्यक्ति को एक पिस्तौल 32 बोर और एक ज़िंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बताया कि 2 जुलाई को सिमरनजीत सिंह निवासी आदर्श नगर, जालंधर के बयान पर थाना डिवीजन नंबर 6, जालंधर में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 109, 62, 61(2) बीएनएस, 25-54-59 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 122, तारीख 02.07.2025 दर्ज किया गया था। मामले की जांच

के दौरान 23 जुलाई को खुफिया सूत्रों और तकनीकी सहायता से सीआईए स्टाफ और थाना डिवीजन नंबर 6 कमिश्नरेट जालंधर की टीमों ने भूपिंदर सिंह उर्फ भिंदा निवासी गरुपर, थाना और, जिला एस.बी.एस. नगर (उम्र लगभग 27 वर्ष) को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 पिस्तौल 32 बोर और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। दोनों आरोपियों की तलाश जारी है।

भारत-इंग्लैंड के बीच होंगे टी20 और वनडे मैच

स्पोर्ट्स डेस्क. मौजूदा समय में भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। भारत का ये इंग्लैंड दौरा यहीं नहीं रुकने वाला है। टीम इंडिया अब अगले साल फिर अंग्रेजों से भिड़ने के लिए इंग्लैंड जाएगी। जहां अगले साल 2026 में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 और वनडे सीरीज खेली जाएगी। जिसकी जानकारी खुद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी है। भारतीय टीम का इंग्लैंड का ये दौरा इस साल खत्म नहीं होगा। अगले साल जुलाई में टीम इंडिया को फिर एक बार वापस आना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 11 जुलाई तक टी20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज में पांच मैच खेले जाएंगे। वहीं इसके तुरंत बाद 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे।

इंग्लैंड बनाम इंडिया टी0 सीरीज़- पहला मैच- 1 जुलाई 2026- बैंक होम रिवरसाइड, डरहम।

फोटो-बीसीसीआई

दूसरा मैच- 4 जुलाई 2026- ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। तीसरा मैच- 7 जुलाई 2026- ट्रेंड ब्रिड, नॉटिंघम। चौथा मैच- 9 जुलाई 2026- सीट यूनिक स्टेडियम, ब्रिस्टल। पांचवां मैच- 11 जुलाई- यूटिलिटा बाउल, साउथहैम्पटन।

इंडिया बनाम इंग्लैंड सीरीज- पहला मैच- 14 जुलाई 2026- एजबेस्टन, बर्मिंघम। दूसरा मैच- 16 जुलाई 2026- सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ। तीसरा मैच- 19 जुलाई 2026- लॉर्ड्स, लंदन।

जालंधर नगर निगम का वरियाणा कूड़ा प्रोजेक्ट : विकास या राजनीतिक भेंट?

• **जालंधर ब्रीज .** विशेष रिपोर्टर

नगर निगम जालंधर ने वरियाणा गांव में अपनी 25 एकड़ खाली जमीन पर शहर का पूरा कूड़ा डालना शुरू किया था। यह जगह जमीन के स्तर से 15 फुट नीचे थी। धीरे-धीरे इस जगह पर कूड़े का ढेर लग गया और इसे दबाकर पक्का करने के लिए नगर निगम ने अपनी जेसीबी मशीनें भी लगा दी थीं, जिनकी निगरानी एक सैनेटरी इंस्पेक्टर और सहायक इंजीनियर करता था। जब कूड़े का स्तर सड़क के बराबर आ गया तो ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी गई। इसके बाद नगर निगम जालंधर ने यह 25 एकड़ जमीन एक कंपनी मैनेजर को 25 साल के लिए सौंप दी। कंपनी ने वहां एक पक्का प्लेटफार्म बना दिया और कूड़े से खाद बनाने के लिए फैक्ट्री भी लगा दी।

लेकिन जालंधर शहर और आसपास के गांवों की किस्मत खराब थी कि यह प्रोजेक्ट राजनीति की भेंट चढ़ गया। जिस कंपनी ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी। जैसे ही अकाली-बीजेपी सरकार आई, प्रोजेक्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां-तहां कूड़ा फेंका जाने लगा।

प्रोजेक्ट के लिए जाने वाली सड़क नगर निगम ने तैयार की थी। कूड़ा प्लेटफार्म पर फेंक कर दूसरी रास्ते से वापिस जाना था, ताकि खाद बनाने की मशीनरी सही ढंग से काम कर सके। एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से इस खाद को मान्यता भी मिल गई थी पर कांग्रेस से जुड़ी कंपनी होने के कारण इस खाद को किसी सरकारी विभाग में नहीं लिया गया। कंपनी ने अपने स्तर पर ही बाजार में खाद बेचनी शुरू कर दी।

कंपनी ने नगर निगम के साथ हुए एग्रीमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया। नगर निगम ने प्लेटफार्म तक पहुंचने वाली सड़क तो बना दी, पर वापसी का रास्ता नहीं बनाया। इसके बाद वहां पब्लिक ने कॉलोनियां काट लीं, हॉस्टल बना दिए और मंदिर तक बना डाला। किसी अधिकारी ने इस पर रोक नहीं लगाई। धीरे-धीरे प्लेटफार्म कूड़े से भर गया। कूड़ा अब प्लेटफार्म के आस-पास और सड़क के किनारे फेंका जाने लगा। कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। बरसात में सड़क खराब हो जाती थी और फिर जहां जगह मिलती थी, वहीं कूड़ा फेंक दिया जाता था।

तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर ने कूड़े के पहाड़ को समतल करने के लिए मिलिट्री से बात की और मिलिट्री के टैंक बुलवाकर कूड़े को दबाया गया, ताकि सड़क के स्तर तक लाया जा सके। इसके बाद मिट्टी डालकर पौधे लगाने का प्लान बनाया गया पर कुछ राजनेताओं ने काम शुरू नहीं होने दिया। एक बार टेंडर भी लगे लेकिन किसी ने भरे नहीं।

जालंधर शहर और आसपास के गांवों की किस्मत खराब थी कि यह प्रोजेक्ट राजनीति की भेंट चढ़ गया। जिस कंपनी ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी। जैसे ही अकाली-बीजेपी सरकार आई, प्रोजेक्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि जहां-तहां कूड़ा फेंका जाने लगा आज स्थिति आपके सामने है...

हर दिन शहर से 500 टन कूड़ा निकलता था जिसे पहले की तरह प्लेटफार्म और आसपास की जगह पर फिर डालना शुरू कर दिया गया। कंपनी की बनाई खाद को भी किसी अधिकारी या नगर निगम की कमेटी ने स्वीकृति नहीं दी, जिससे कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए।

10 साल अकाली सरकार रही, फिर कांग्रेस सरकार आई तो थोड़ी उम्मीद जगी कि खाद को सरकारी विभागों में या प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा सकेगा। लेकिन कूड़ा इतना ज्यादा हो गया कि फिर पहाड़ बन गए और किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। बरसात में कूड़े से निकलने वाला तेजाब और पानी सड़क पर जमा हो जाता है और सफाई मुश्किल हो जाती है।

नगर निगम ने पास ही सरकार से जमीन खरीद कर वहां कूड़े की रीसाइक्लिंग के लिए एक शैड और कुछ मशीनें लगाईं, जो अब तक वहीं खड़ी हैं। खबरें हैं कि नगर निगम अभी और जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा है।

अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखना यह होगा कि यह प्रोजेक्ट फिर से शुरू होगा या राजनीति की भेंट चढ़ा रहेगा। वरियाणा कूड़ा प्रोजेक्ट आज भी जालंधर शहर की एक अधूरी योजना और राजनीतिक खींचतान का शिकार है। अगर सरकार और प्रशासन ने मिलकर ठोस कदम नहीं उठाए तो यह न सिर्फ शहर की सफाई व्यवस्था के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा संकट बना रहेगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.